

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 720वीं बैठक दिनांक 05/02/2024 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :-

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. **Case No 7918/2020 Shri Balveer Tomar, OIC, Junior General Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.0 ha. (30,000 cum per annum) (Khasra No. 574), Village - Tila, Tehsil - Naugaon, Dist. Chhatarpur (MP) (EIA)**

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii(a & b) dated 14-Sep-2016.

- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Tila 2	7918/20	20-Mar-23	30-June-2023	19-Mar-2028	30000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेगें तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

2. **Case No 7917/2020 Shri Balveer Tomar, OIC, Junior General Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 6.0 ha. (20000 cum per annum) (Khasra No. 1540/1), Village - Padwaar, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) (EIA)**

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.
- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	EC quantity (Cum)	CER/Plantation
Padwaar-2	7917/20	07-Mar-23	30-June-2023	06-Mar-2028	20000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

06 माह में समीक्षा की जाएं तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जाएं।

3. **Case No 7903/2020 Shri Balveer Tomar, OIC, Junior General Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 5.20 ha. (70000 cum per annum) (Khasra No. 332), Village - Dhaurara, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) [56814] (EIA)**

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.
- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	ECquantity (Cum)	CER/Plantation
Dhaurara	7903/20	07-Mar-23	30-June-2023	06-Mar-2028	70000	Partially completed

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 फरवरी 2024

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

4. **Case No 7899/2020 Shri Balveer Tomar, OIC, Junior General Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 14.0 ha. (100000 cum per annum)**

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 फरवरी 2024

(Khasra No. 697/1), Village - Nehra, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP)
[56817] (EIA)

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.
- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	ECQuantity (Cum)	CER/Plantation
Nehra	7899/2020	20-Mar-23	30-June-2023	19-Mar-2028	100000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 फरवरी 2024

3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

5. Case No 7974/2020 Shri Balveer Tomar, OIC, Junior General Manager, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 10.0 ha. (80000 cum per annum) (Khasra No. 472/2), Village - Baarbandh-4, Tehsil - Gaurihar, Dist. Chhatarpur (MP) [56808] (EIA)

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.
- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	ECquantity (Cum)	CER/Plantation
Baarbandh-4	7974/20	09-Feb-23	30-June-2023	08-Feb-2028	80000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

- दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षों, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
 7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
 8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
 9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
 10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

6. **Case No 8376/2021 Shri Puran Lakshkar, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 8.093 ha. (76000 cum per annum) (Khasra No. 120), Village - Nahlai, Tehsil - Rehti, Dist. Sehore (MP) [61480] (EIA)**

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.

- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	ECquantity (Cum)	CER/Plantation
Nahlai	8376/2021	15-Jun-22	30-June-2023	14-Jun-2027	76000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।
10. राज्य /संभाग /जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावें तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावें।

7. Case No 8900/2022 Shri Arjun Shrivastava, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 23.0 ha. (285855 Cum per annum) (Khasra No. 300, 311), Village - Jahajpura-3, Tehsil - Rehti, Dist. Sehore (MP) [70443] (EIA)

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.
- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of	Case No	EC issued	EC validity	To be	ECQuantity	CER/Plantation
---------	---------	-----------	-------------	-------	------------	----------------

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

Sand Mine		Date	mentioned in EC	extended upto	(Cum)	
Jahajpura-3	8900/2022	15-Jun-22	30-June-2023	14-Jun-2027	285855	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 फरवरी 2024

8. Case No 8907/2021 Shri Arjun Shrivastava, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 5.140 ha. (24510 Cum per annum) (Khasra No. 146), Village - Charua, Tehsil - Rehti, Dist. Sehore (MP) [70470] (EIA)

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.
- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	ECquantity (Cum)	CER/Plantation
Charua	8907/2021	15-Jun-22	30-June-2023	14-Jun-2027	24510	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 फरवरी 2024

the concerned District Mining Officer.

2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
 3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
 4. ई.सी. की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
 5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर. के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर. में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
 6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
 7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
 8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
 9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
 10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।
9. **Case No 8905/2022 Shri Arjun Shrivastava, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 10.0 ha. (171000 Cum per annum) (Khasra No. 155/1/1), Village - Janwasa-3, Tehsil - Budhni, Dist. Sehore (MP) [70532] (EIA)**

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.
- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	ECquantity (Cum)	CER/Plantation
Janwasa-3	8905/2021	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	171000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।

6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

10. **Case No 8906/2021 Shri Arjun Shrivastava, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 12.950 ha. (198300 Cum per annum) (Khasra No. 104/2), Village - Somalwada, Tehsil - Budhni, Dist. Sehore (MP) [70434] (EIA)**

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.
- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	ECQuantity (Cum)	CER/Plantation
Somalwada	8906/2021	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	198300	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

11. **Case No 8908/2021 Shri Arjun Shrivastava, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 16.187 ha. (216000 Cum per annum) (Khasra No. 893/852, 852), Village - Sardarnagar, Tehsil - Budhni, Dist. Sehore (MP) [70484] (EIA)**

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.
- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

shown by PP.

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	ECquantity (Cum)	CER/Plantation
Sardarnagar	8908/2022	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	216000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

12. Case No 8904/2021 Shri Arjun Shrivastava, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 20.995 ha. (199329 Cum per annum) (Khasra No. 263/212), Village - Mahukala, Tehsil - Budhni, Dist. Sehore (MP) [70450] (EIA)

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.
- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	ECQuantity (Cum)	CER/Plantation
Mahukala	8904/2022	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	199329	Partially completed

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 फरवरी 2024

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

13. Case No 8901/2021 Shri Arjun Shrivastava, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 फरवरी 2024

**Quarry in an area of 15.0 ha. (202380 Cum per annum) (Khasra No. 155/1/1),
Village - Janwasa-4, Tehsil - Budhni, Dist. Sehore (MP) [70527] (EIA)**

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.
- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	ECquantity (Cum)	CER/Plantation
Janwasa-4	8901/2022	15-Jun-2022	30-June-2023	14-Jun-2027	202380	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 फरवरी 2024

3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षों, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

14. Case No 9333/2022 Shri Satendra Singh, Junior Manager (OIC), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 14.0 ha. (200000 Cum per annum) (Khasra No. 225/1), Village - Satrawan-1, Tehsil - Baraily, Dist. Raisen (MP) [82094] (EIA)

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.
- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	ECQuantity (Cum)	CER/Plantation
Satrawan-1	9333/2022	06-April-23	30-June-23	05-April-28	200000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शायें गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।

7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

15. **Case No 8419/2021 Shri Arjun Shrivastava, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 16.667 ha. (74822 cum per annum) (Khasra No. 352/340), Village - Baghwada, Tehsil - Budhni, Dist. Sehore (MP) [62072] (EIA)**

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.
- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

(KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.

- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	ECquantity (Cum)	CER/Plantation
Baghwada	8419/2021	15-Jun-2022	30-June-23	14-Jun-2027	74822	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।
10. राज्य / संभाग / जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

16. Case No 9324/2022 Shri Satendra Singh, Junior Manager (OIC), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Bharkachha Kalan Sand Quarry in an area of 12.0 ha. (1,50,000 cum per annum) At Khasra No.-614 near Village- Bharkachha Kalan, Tehsil- Badi, District- Raisen [290173] (EIA)

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.
- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of	Case No	EC issued	EC validity	To be	ECquantity	CER/Plantation
---------	---------	-----------	-------------	-------	------------	----------------

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

Sand Mine		Date	mentioned in EC	extended upto	(Cum)	
Bharkachha Kalan	9324/2022	06-April-2023	30-June-23	05- April-2028	150000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

17. Case No 9332/2022 Shri Satendra Singh, Junior Manager (OIC), M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 फरवरी 2024

Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 15.0 ha. (120000 Cum per annum) (Khasra No. 398), Village - Andiya, Tehsil - Udaipura, Dist. Raisen (MP) [81964] (EIA)

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.
- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	ECquantity (Cum)	CER/Plantation
Andiya	9332/2022	06-April-2023	30-June-23	05-April-2028	120000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 फरवरी 2024

2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षों, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

18. Case No 8903/2021 Shri Arjun Shrivastava, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 18.107 ha. (171000 Cum per annum) (Khasra No. 352/340), Village - Baghwada, Tehsil - Budhni, Dist. Sehore (MP) [70488] (EIA)

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.
- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	ECquantity (Cum)	CER/Plantation
Baghwada	8903/2022	15-jun-2022	30-June-23	14-jun-2027	171000	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।

6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षों, झाड़ियों (Shrub), लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

19. **Case No 8902/2022 Shri Arjun Shrivastava, Jr. Manager, OIC, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Paryawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 16.10 ha. (188613 Cum per annum) (Khasra No. 79), Village - Nilkanth, Tehsil - Nasrullaganj, Dist. Sehore (MP) [70567] (EIA)**

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.

- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	ECquantity (Cum)	CER/Plantation
Nilkanth	8902/2022	15-Jun-2022	30-June-23	14-Jun-2027	188613	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन् कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।

9. रेत खनन् कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की जा सकेगी ।
10. राज्य/संभाग/जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

20. **Case No 8393/2021 Shri Shashi Singh, Authorized Person, M/s The MP State Mining Corporation Limited, Parvawas Bhawan, Block-A, 2nd Floor, Jail Road, Arera Hills, District-Bhopal (MP)-462011 Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 10.0 ha. (113400 cum per annum) (Khasra No. 207), Village - Sansarkheda-2, Tehsil - Saikheda, Dist. Narsinghpur (MP) [60792] (EIA)**

The above project pertains to sand mining and were accorded EC by MPSEIAA which was valid up to 30/06/2023 as per the Mining Lease. In this regards M.P. State Mining Corporation Ltd. vide letter no. 1371 dated 22.01.2024 & letter no. 1415 (A) dated 05.02.2024 and Additonal Advocate General letter no.1295 dated 08.01.2024 submitted in the SEAC. The above case has been received from SEIAA for extension of the validity of EC for 05 years with effect from date of issue. Based on the scrutiny and submissions made by the M.P. State Mining Corporation following observations were made by the Committee:

- By virtue of size and locations the projects fall under category B-1, accordingly EIA was carried out for this project and based on the EIA / EMP appraisal EC was granted to this project. The validity of the EC was co-terminus with the Lease thus the EC validity in this the cases has expired on 30/06/2023.
- The leases have been accorded in the name of M.P. State Mining Corporation Ltd with vide M.P Govt. order dated 31-May-2023 for the period of 10 years.
- The application for extension of the validity of EC has been made before SEIAA within less than 90 days after validity period. Thus, this case was found to be eligible for extension of the validity period as per the provisions of notification MOEF&CC (point 9-iii (a & b) dated 14-Sep-2016.
- The sensitivity of the locations has been examined through the Google images (KML image) of the sites. It was observed that there are no additional sensitive features located within 01 Km of the lease areas as was observed before committee.
- The compliances of the EC conditions of the old EC were partially complied.
- The KML image of the lease area based on coordinates based on Mining Plan was shown by PP.

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

PP further submitted following detail about the prior EC:

Name of Sand Mine	Case No	EC issued Date	EC validity mentioned in EC	To be extended upto	ECquantity (Cum)	CER/Plantation
Sansarkheda 2	8393/2021	08-Feb-2023	30-June-23	07-Feb-2028	113400	Partially completed

Based on the observations and submissions the cases may be considered for extension of the EC validity subject to the following special conditions:

1. Compliance of the condition of the EC shall be ensured by the the State Mining Corporation. The compliances report shall be submitted after due certification of the concerned District Mining Officer.
2. CER utilization certificate duly verified by the concerned Mining Officer shall be furnished along with the EC compliance reports.
3. Necessary Permissions shall be obtained from MPPCB for setting up the linked stock yards.
4. ई.सी की समस्त शर्तों का एवं दर्शाये गये कार्यों को पूर्ण कर विस्तृत पालन प्रतिवेदन खनिज अधिकारी से प्रमाणिकृत करवाकर प्रत्येक 06 माह के अंदर सिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तथा वृक्षारोपण का कार्य सितम्बर 2024 के पूर्व पूर्ण करेंगे।
5. खदान क्षेत्र की रिप्लेनिशमेंट स्टडी, खनिज अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष कराई जावेगी एवं उपलब्ध मात्रा के आधार पर खनन कार्य डी.एस.आर के अनुसार परियोजना प्रस्तावक/खनिज अधिकारी सुनिश्चित करें परन्तु किसी भी स्थिति में स्वीकृति डी.एस.आर में दर्शायी मात्रा एवं अधिक मात्रा में रेत खनन नहीं किया जावे।
6. नदी के किनारों से न्यूनतम 7.5 मीटर तक स्थित वृक्षो, झाड़ियों (Shrub), लताओ को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
7. रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषको से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
8. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई Prone and other sensitive creatures Breeding Center तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे।
9. रेत खनन कार्य अवधि के दौरान कार्बन फुटप्रिंट के प्रभाव के आधार पर उसको दूर किये जाने के उपाय किये जायेंगे। अन्य विकल्पों के साथ आसपास के 01 कि.मी. जिसमें व्यवस्थाओं के साथ आसपास 01 किलोमीटर में किसानों के खेतों में खड़े वृक्षों में होने वाले कार्बन संचयन के विषय में परियोजना प्रस्तावक के स्तर पर कार्बन ट्रेडिंग भी प्रस्तावित की

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

जा सकेगी ।

10. राज्य / संभाग / जिला स्तरीय पर्यावरण प्रकोष्ठ स्तर पर ई.सी. की शर्तों के पालन हेतु प्रत्येक 06 माह में समीक्षा की जावे तथा शर्तों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रयास किया जावे।

21. **Proposal No. SIA/MP/IND1/458989/2024 M/s Samruddha MineChem Private Limited, Floor – 6 A Block, Shivsagar Estate Dr. A.B Road , Mumbai (Maharastra) – 400018. Prior Environment Clearance for the Proposed Beneficiation plant upto a level from 16 to 17.5% % of Phosphate content and will be converted up to 32.7 to 33%% of Phosphate in the concentrate at 171, 172, 173, 178, 179, 182, 183, 185, 186, 187, 189,200, 201, 202, 259, 263, 264, 265, 266, 282 and 283, Area - 13.49 ha., Land Required - 2.19ha .Capacity : 1000000 TPA Village- Kachaldara, Tehsil- Meghnagar, Distt. – Jhabua (M.P.). Village -Kachaldara,, Meghnagar District Jhabua (M.P.), Cat. : 2(b) Mineral beneficiation. (TOR).**

This is an ore beneficiation project comprising beneficiation of Phosphate content from 16% to 17.5% % to 32.7% to 33% . The project is covered under the provisions of EIA notification as item no. 2 (b), hence requires prior EC from SEIAA. Application submitted by the PP was forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP.

The case was presented by Env. Consultant Shri Umesh Mishra from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal (MP) and PP Shri Ashish Bahdur Director. Wherein PP submitted that M/s. Samruddha Minechem Private Limited proposes to construct a 70 T (rated) & 77 TPH (Design) feed capacity Rock Phosphate Beneficiation plant in the Village - Kachaldara, Meghnagar District Jhabua in the state of Madhya Pradesh. The Low Grade of rock phosphate fines coming from nearby mines will be the main input to the proposed Beneficiation plant upto a level from 16 to 17.5% % of Phosphate content and will be converted up to 32.7% to 33% of Phosphate in the concentrate.

Following details wer submitted by PP on Parivesh portal :

SN	Projects Details		Remarks
1.	Online Proposal No	SIA/MP/IND1/458989/2024.	
2.	Proposal /Activity Name	SAMRUDDHA MINECHEM PRIVATE LIMITED, Floor-6, A Block, Shivsagar Estate, Dr. A. B. Road, Nr. Nehru Centre Worli, Mumbai, Mubai City, (Maharastra) 400018.	
3.	Location of Project	The M P. State Mining Corporation Ltd , 171, 172, 173, 178, 179,	

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 05 फरवरी 2024

		182, 183, 185, 186, 187, 189, 200, 201, 202, 259, 263, 264, 265, 266, 282 and 283, Village- Kachaldara, Tehsil- Meghnagar, Distt. – Jhabua (M.P.).Area- 13.49 ha., Land Required - 2.19ha Capacity : 1000000 TPA.Cat. : 2(b) Mineral beneficiation.
4.	Lease Status	New. Fresh ToR.
5.	Proposed ToR	Submitted
6.	LOI	Letter No.- 11262 date 09 / 10 /2023.
7.	Project Cost.	22998.00 Lakhs.
8.	Lease Area (Govt./ Pvt.)	13.49 ha.,
9.	Production Qty. in M ³ /Y	Rock Phosphate Concentrate : 500000 TPA.
10.		PP Submit letter dated 13/12/2023.
Documentary Details		
11.	DFO NOC	PP Submit Letter No.- 5665 date 29 / 11 /2023.
12.	Inter State Boundary details	-
13.	Water NoC	PP Submit Letter No.- 5665 date 29 / 11 /2023.
14.	Env. Consultant	PP Submit Letter No.- 1696 date 20 / 11 /2023.
15.	CTO/CTE	will be obtained after EC.
16.	PFR	Submitted.

The PP further stated that the project area are in two parts.

After presentation, committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC with following additional TOR and as per Annexure-D:

1. Drone photography of the area .
2. Elaborate Technology used for beneficiation.
3. Carbon foot print analysis for proposed production shall be studied and discussed in EIA report.
4. Water balance with source of water to be furnished along with the consent/ permission for supply of requisite quantum of water from the competent authority.
5. Complete ore analyses to be furnished.
6. Environmentally sustainable disposal of the Tailing residue to be addressed in the EIA report.
7. Mass balance for the solid waste (tailings residue) for entire plant to be presented in the EIA Report.
8. Inventory of the trees with photographs existing within the project area with species, height, girth and proposal for conservation with EIA report.
9. Proposal for power generation from non- conventional sources i.e. solar power etc. to achieve 30% of the total power consumption.
10. Impacts study on agriculture land and its production which is in the surrounding of the project area with EIA report.

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

11. Transportation plan with the EIA report.
12. Complete details of the Tailing Pond including the lining, dimensions, capacity and proposed locations of peizometers etc. with pollution control devises proposed in crusher and other similar units shall be detailed out in the EIA report.
13. Appropriate Garland drains to be provided around all the heaps in the premises along with the settling / collection tank connected to the garland drains- complete plan to be furnished in the report.
14. Lechate study should also be carried out on suitable locations.
15. Detailed plant layout on A3 sheet with mass balance shall be submitted with EIA report.

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु

Corrigendum

1. **Case No 703/2012 M/s. Opal Developers Shalimar house, Malviya Nagar, Raj Bhawan Road-Bhopal-M.P. Residential project at Plot No/Survey No/Khasra No : 429, 430/1, 400/2, 401/2, 431/1/2, 431/1/3, Bawadiakalan, Teh-Huzur, Distt-Bhopal. Modification in EC. Cat. 8(a) Building Construction Project.Extension of validity of EC.**

The case has been submitted for for extension of validity of the existing EC for Residential Project at Plot No/Survey No./Khasra No. – 429, 430/1, 400/2, 401/2, 431/1/2, 431/1/3, Bawadiakaln, Tehsil – Huzur, District – Bhopal by M/s Opal Developers Shalimar House and State: Madhya Pradesh

In the SEAC 709th meeting dated 04.01.2024 meeting the committee considered and granted extension of the EC validity for one year.

PP requested vide their letter 05.01.2024 and Environmental Consultant of PP requested before the coomiittee in the the SEAC 720th meeting dated 05.01.2024 wherein PP submiited that -

- Regarding the extension of the Validity of EC for 2 years as per the OM dated 27.11.2020 Validity Extension Due to COVID.
- “9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the validity of prior environmental clearances granted under the provisions of this notification in respect of the projects or activities whose validity is expiring in the Financial Year 2020-2021 shall deemed to be extended till the 31st

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

March, 2021 or six months from the date of expiry of validity, whichever is later. Such extension is subject to same terms and conditions of the prior environmental clearance in the respective clearance letters, to ensure uninterrupted operations of such projects or activities which have been stalled due to the outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control”.

- Dated 18.01.2021 Validity Extension Due to COVID (II) “9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus (COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.”.
- As per the Extension Notification S. No. 1807 (E) Dated 12.04.2022 and OM dated 27.11.2020 & 18.01.2021 the Validity of the present EC is 25.06.2024.
- So, we requested to the SEAC Committee to kindly grant us the Corrigendum in favor of Extension of Validity of EC letter for two years for this case.

In light of above facts and submission made by consultant before the committee is of the view that considering request of PP and considered for extend the validity for two years for this case.

2. **Case No 10342/2023 Shri Anand goenka R/o Goendka Bhavan, Station Road, District Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Manganese Ore Mine in an area of 8.10 ha. (Expansion from 3430 TPA to 17,010 TPA) (Khasra No. 523/1, 523/2, 523/3), Village-Pauniya, Tehsil-Katangi, District-Balaghat (MP)**

समिति के संज्ञान में आया कि 673वीं बैठक दिनांक 01/09/2023 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा टॉर में Manganese Ore- Expansion from 3430 TPA to 13580 TPA उल्लेखित हो गया है जबकि अनुमोदित माइन प्लान, परिवेश पोर्टल पर आवेदन, पीएफआर में उत्पादन क्षमता Manganese Ore- Expansion from 3430 TPA to 17,010 TPA) है ।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 673वीं बैठक दिनांक 01/09/2023 को टॉर अनुशंसित Manganese Ore-Expansion from 3430 TPA to 13580 TPA के स्थान पर Manganese Ore-Expansion from 3430 TPA to 17,010 TPA पढ़े जाने का निर्णय लेती है, शेष अन्य शर्तें यथावत रहेंगी ।

3. सिया का पत्र क्रमांक 2681 दिनांक 29/01/2024 प्रकरण क्रमांक 10322/2023 की शिकायत प्रेषित की गई है।

Shri Girish Khandwekar, Junior Manager (General), C.T.T Nagar, Nehru Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Bhanjakhedi-2 Sand Deposit in an area of 4.00 ha. (25000 cum per year) (Khasra No. 76), Village-Bhanjakhedi-2, Tehsil-Khatgaon, District-Dewas (MP).

शिकायत का परीक्षण

- उक्त प्रकरण के संबंध में सिया की 823वीं बैठक एवं 824वीं बैठक में निर्णय लिया गया
- प्रकरण में प्रमोद यादव द्वारा की गई शिकायत के संबंध में कलेक्टर जिला देवास द्वारा पत्र क्रमांक 2411 दिनांक 07/12/2023 के माध्यम से प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आधार पर सिया द्वारा 823वीं बैठक दिनांक 29/12/2023 में ई.सी. जारी करने की अनुमति प्रदान की गई थी परन्तु ई.सी. जी नहीं की गई है।
- शिकायतकर्ता श्री प्रमोद यादव द्वारा सिया कार्यालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेख किया गया है कि कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास द्वारा पत्र दिनांक 25/11/2023 के माध्यम से शिकायतकर्ता को मौका स्थल पर दिनांक 30/11/2023 को सुबह 11 बजे उपस्थित रहने हेतु कहा गया यह कि नियत दिनांक को मैं उपस्थित रहा तत्समय उपस्थित पुलिस के सदस्य द्वारा मेरे से जबरदस्ती कोरे कागज पर दस्तखत करवा लिये गये।
- शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में अपने अधिवक्ता रोहित शर्मा के माध्यम से लीगल नोटिस दिनांक 05/01/2024 को प्रेषित किया गया है।

समिति द्वारा उक्त सिया द्वारा प्रेषित शिकायत के संबंध में यह निर्णय लिया कि सेक की पूर्व बैठक 688वीं दिनांक 12/10/2023 में सिया के पत्र क्र. 1648 दिनांक 11/10/2023 के माध्यम से प्रेषित शिकायत का तकनीकी बिन्दु पर परीक्षण किया गया था।

सिया के पत्र क्रमांक 2681 दिनांक 29/01/2024 प्रकरण क्रमांक 10322/2023 के संबंध में भेजी शिकायत के बारे में समिति का निर्णय है कि यह तकनीकी बिन्दु न होकर प्रशासनिक एवं विधिक मामलों से संबंधित है अतः प्रकरण का निपटान करना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास से करना उचित होगा।

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट आगर-मालवा रेत खदान की संशोधित रिपोर्ट

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

खनिज निरीक्षक सुश्री खुशबु वर्मा द्वारा अपने कार्यालय कलेक्टर आगर मालवा द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट - रेत खदान की संशोधित रिपोर्ट पत्र क्रमांक 77 दिनांक 16/01/2024 के माध्यम से प्रस्तुत की गई। खनिज अधिकारी ने अवगत कराया कि म.प्र. राज्य खनिज निगम को पत्र क्रमांक रेत/2023/641 दिनांक 28.08.2023 एवं परिवेश एनवायरनमेंट इंजीनियर सर्विसेस का पत्र दिनांक 19.08.2023 से संशोधन हेतु निर्देश दिए गए। जिसके पालन में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार आवश्यक संशोधन किये गए :-

1. सस्टेनेबल सेन्ड माईनिंग मेनेजमेंट गाईडलाईन 2020 के अनुसार खदानों का पूर्णगठन (पूर्व से घोषित 11 खदानों में से 07 खदानों को सूची पृथक किया गया) किया गया।
2. शेष 04 खदानों में से 02 खदानों का खनिज एवं क्षेत्र उपलब्धता के आधार पर क्षेत्रफल में संशोधन किया गया।
3. खदानों के पूर्ववत त्रुटिपूर्ण कॉर्डिनेट को नवीन खनन योजना अनुसार संशोधित किया गया।
4. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (खनिज रेत) में परियोजना प्रस्तावक का नाम, खसरा, रकबा, कॉर्डिनेट, रेत पूर्णभरण और 60% खनन योग्य उपलब्ध खनिज की जानकारी अद्यतन की गई है।
5. अतः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट गठित समिति द्वारा अनुमोदित की जाकर अद्यतन संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन की अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र के साथ संप्रेषित है।

उपरोक्तानुसार प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज (संशोधित) समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जिसको समिति द्वारा मान्य किया गया एवं जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला- आगर मालवा रेत खनिज (संशोधित) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित किया जाये।

सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 05 फरवरी 2024

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in-situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCC's Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna".
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The undertaking inter-alia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carried out in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and discussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concerned CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक दिनांक 05 फरवरी 2024

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
37. **FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.**
- Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
 - Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
 - A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
 - The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.
38. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊँचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्ही प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
40. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबैक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
41. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दूष्प्रभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बड़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड के एक्जैम्पल में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
42. CER योजना के अंतर्गत जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6-6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करे।
43. अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैचैस की स्थिति।

खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

- नोट 1 :-** स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।
- नोट 2 :-** विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3 :-** पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमी को बनाये रखने हेतु मल्टिचिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

720वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 05 फरवरी 2024

नोट 4 :- परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्कूल/ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जायें।

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चैनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम	गोलाई न्यूनतम
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05-10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट - 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट - प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर।
2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पाँचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतुर्दम उतममकपदह बमदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे